THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

Government is aware of media reports about the said and other similar statements made from time to time by terrorist outfits flourishing in Pakistan. Government has taken up with Pakistan that they should stop support to cross border terrorism and abandon abetment of terrorism and its anti-India propaganda to create a conducive atmosphere for the implementation of the Lahore process and a resumption of the composite dialogue. The international community has also been kept apprised of Pakistan's continued support to terrorism.

2. All measures necessary to preserve the security and territorial integrity of the country continue to be taken.

Change in National Security after Kargil Conflict

‡*353. SHRI SATISHCHANDRA SITARAM PRADHAN: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item which appeared in Nav Bharat Times dated 8th August, 1999 under the caption, "Kargil Shangharsh ke bad Rashtriya Surksha Main Badlaw Jaruri, General Sood"; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

Government are aware of the news-item appearing in 'Navbharat Times' expressing certain views about various aspects of National security management.

National Security Council with its sub-structures viz. the National Security Advisory Board, Strategic Policy Group and the National Security Council Secretariat provide an effective channel for integrated thinking and coordinated application of the political, millitary, diplomatic, scientific and technological resources of the State to protect and promote national security goals and objectives. The inputs generated through inter-Ministerial coordination and integration of views fron both within the Government and experts outside the Government help in the formulation of National security policies by the Government.

In accordance with the Government of India (Transaction of Business) Rules, 1961 as amended from time to time, all matters relating to national security are considered and decisions taken by the Government. Further, Government review all developments impinging upon Ir 'ia's security on a regular basis and take appropriate decisions after

‡ Starred Question Nos. 341 and 353 were taken together.

examining all pros and cons. While doing so, the views expressed in the media and elsewhere are also duly considered by the Government.

MR. CHAIRMAN: I think Question No. 341 and Question No.353 are similar. So, these may be taken together.

SHRI SATISHCHANDRA SITARAM PRADHAN: Sir, Question No. 353 may also be taken together.

MR. CHAIRMAN: I have already spoken before you spoke.

श्री जनेश्वर मिश्र: मान्यवर, मंत्री जी ने जो बयान दिया है, उसके पहले वाक्य में है कि सरकार मीडिया रिपोर्ट की जानकारी रखती है। हमने सवाल मीडिया रिपोर्ट के बारे में नहीं पूछा था। हमने सवाल पूछा था कि पाकिस्तान में एक आतंकवादी संगठन काम कर रहा है, जो पहले अफगानिस्तान में काम करता था, अब पाकिस्तान में नाम बदलकर काम कर रहा है और उसके प्रधान ने कहा है कि जैसे ही बर्फ पिघल जाएगी वैसे ही कारगिल पर फिर से हमला करेंगे और कब्जा करेंगे। मान्यवर, यह देश की सुरक्षा का सवाल है और इसलिए मीडिया की रिपोर्ट के आधार पर अगर भारत सरकार कोई कार्रवाई करती है और कदम उठाती है तो वह बहुत ही खतरनाक बात हो जाएगी। जब किसी देश से रिश्ते अच्छे नहीं रहते तो दुश्मन के घर में रोटी क्या पकती है, यह भी जानकारी रखी जाती है। माननीय रक्षा मंत्री जी 'नताली' का नाम जानते होंगे, रूस की यह लड़की हिटलर के घर में खानसामा का काम करके खुफियागिरी करती थी। इस समय पाकिस्तान में कितने आतंकवादी संगठन भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, क्या भारत सरकार के पास कोई खुफिया एजेंसी है जो इस बात की जानकारी रखती हो कि उनकी गतिविधियां क्या हैं और किस सीमा तक पाकिस्तान की सरकार उन आतंकवादी संगठनों को मदद करती है? मान्यवर, यह बात बहुत ही सफाई के साथ देश के सामने आनी चाहिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: सभापति महोदय, मीडिया रिपोर्ट्स के बारे में इसलिए कहना जरूरी था कि हमारे पास हरकत-उल-मुजाहिद्दीन नाम की इस संस्था ने जो भी घोषणा की है, उसके बारे में जो जानकारी है, वह मीडिया के माध्यम से ही मिली हुई जानकारी है, उनकी तरफ से हमें कोई लिखित में नहीं आया है और न ही अन्य कोई ऐसी चीज़ हमने उनके खेमे से ली है। हां, खुफिया तंत्र की ओर से हमें जानकारी आती है, उसमें क्या संभवानाएं हैं आदि-आदि चीज़ को लेकर, लेकिन उनका जो बयान है वह बयान केवल मीडिया के माध्यम से ही हम लोगों को मिला है। सभापति जी, जहां तक उनके बयान का, उनकी तरफ से चलने वाली जो भी कार्रवाइयां हैं, उनका और उनके जैसे जो अनेक संगठन और भी हैं, जो इस प्रकार की बातें कहते हैं और इस प्रकार के कुछ कार्य वे करते भी हैं, उनका सवाल है, तो यह एक प्रकार का प्रॉक्सी वार है, जिसको हम लड़ रहे हैं और पिछले 10 साल से यह जो कश्मीर में इस प्रकार का कांड चल रहा है, उसमें कई संगठनों का निर्माण हुआ है, कई खत्म हुए हैं और यह एक प्रकार का लगातार प्रॉक्सी वार चला हुआ है, जिसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। उसका सामना करने के लिए जहां तक हम लोगों की तैयारी की बात है, तो उसके लिए सेना तैनात है और काम कर रही है। कोई दिन नहीं जाता, जब कि कश्मीर में ऐसी हरकतें नहीं होती हों और उनका सामना नहीं होता हो।

सभापति जी, इस साल में अभी तक विदेशी संगठनों के ज़रिए या भीतरी आतंकवादियों के ज़रिए से जो ऐसे प्रयास हुए हैं और उनमें अभी तक जो लोग मारे गए हैं, उनकी संख्या 1,006 है। ...(**व्यवधान**).

श्री जनेश्वर मिश्र: हमने पूछा है कि क्या भारत सरकार के पास कोई ऐसी एजेंसी है? हमारी सरहद के पार इस देश से जिसके रिश्ते किसी वजह से बिगड़ गए हैं कितने आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं, उनकी गतिविधियां क्या हैं और पाकिस्तान की सरकार उनकी क्या मदद कर रही है?

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: I think it is a secret.

MR. CHAIRMAN: The Minister is quite capable of replying. Your intervention is not required.

श्री जार्ज फर्नान्डीज: सभापति महोदय, मैंने शुरू में ही कहा कि हमारे पास जो जानकारी आती है वह जानकारी खुफिया विभागों से आती है कि उन लोगों के क्या-क्या हथकंडे हैं, किन-किन कार्यों में वह लगे हुए हैं और उसी आधार पर हम लोगों की कार्रवाई भी होती है। इसलिए मैं यह बतला रहा हूं कि यह जो साल पूरा हो रहा है, इस साल में एक हजार छः लोग मारे गए जो इस प्रकार की हरकतें करने के लिए कश्मीर के भीतर घुस चुके थे या कश्मीर के भीतर से हरकतें कर रहे थे।

श्री जनेश्वर मिश्र: हमारे सवाल का ठीक से जवाब नहीं आया। लेकिन अभी सरकार ने जवाब दिया है, लिखित जवाब है उसमें कहा है कि इस तरह के बयान के बारे में पाकिस्तान को हमने खबर की है कि ऐसा बयान न आए। पाकिस्तान के पलटन के इस समय जो मालिक है, जो देश के मालिक हैं उन्होंने अपने बयान में खुद कहा है कि कश्मीर के सवाल पर अगर जरूरत पड़ी तो आणविक हथियारों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। अब उसी मालिक से यह फरियाद की जा रही है कि तुम्हारे यहां आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं। उनका यह बयान यहां के सभी अखबारों में छप चुका है कि अगर जरूरत पड़ी तो कश्मीर के सवाल पर आणविक हथियारों का भी इस्तेमाल किया जाएगा और इसके लिए देश तैयार रहे, वहां यह बोली बोली जा रही है। वह आतंकवादी नहीं हैं, उस देश के मालिक हैं और उनके यहां हम फरियाद आतंकवादियों के लिए कर रहे हैं, यानी 'ए' टीम जो सबसे खतरनाक है उसके यहां जाकर के हम 'बी' टीम के छोटे से फाउल की शिकायत कर रहे हैं। सरकार की यह नीति बन गई है।

हमारा सेकेंड सप्लीमेंट्री यह है कि यह बात तो आप मान लीजिए कि आतंकवादी आए और हम लोग सो रहे थे। किसी चरवाहे ने बताया, किसी हलवाहे ने बताया और रक्षा मंत्री जी ने बयान दे दिया कि अगर तुम वापिस जाना चाहते हो तो हम तुमको सुरक्षित रास्ता दे देंगे। तो क्या भारत सरकार, अगर यह फिर किसी तरह से घुस आए तो कोई सुरक्षित रास्ता उनके वापिस लौट जाने के लिए बना रही हैं?

MR. CHAIRMAN: That is not a question. You need not reply.

श्री सतीश प्रधान: सर, हम रोज अखबार पढ़ते हैं और अखबारों में अलग-अलग सी न्यूज कारगिल के संबंध में आती हैं, कभी हम सुनते हैं कि चीन की गतिविधियां बढ़ गई हैं, कभी कारगिल के अगल-बगल में दहशत वाले लोगों ने हमारे ऊपर अटेक किया है, ऐसी न्यूज़ आती हैं। नव भारत टाईम्स में एक न्यूज़ आई है जिस कारण मुझे यह सवाल पूछना पड़ रहा है। हमारे पूर्व थल सेनाध्यक्ष लेफ्टीनेंट जनरल बी.के. सूद ने इंटरव्यू में बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का एक पूर्णकालीन सलाहकार होने की आवश्यकता है, एक पूर्णकालीन सक्षम सचिवालय भी उसके लिए आवश्यक है, ऐसा बताया गया है। मैं आदरणीय रक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि हमारे पास जो व्यवस्था है-एडवाइजरी बोर्ड है, स्ट्रेटेजिक पौलिसी ग्रुप है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सैक्रेटरिएट है, फिर भी ऐसी क्यों जरूरत पूर्व सेनाध्यक्ष को लगने लगी जिसकी वजह से एक पूर्णकालीन, जो कि वहां अफसर नहीं है, ऐसे बाहर के आदमी को उस समिति में

लेने की आवश्यकता है और उसके लिए पूर्णकालीन सैक्रेटरिएट भी उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है? चूंकि यह पूर्व सेनाध्यक्ष ने बयान दिया है इसलिए आप इस पर कुछ प्रकाश डालें।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: उनके मन में क्या बात है उस पर हम कोई रोशनी डालने की स्थिति में नही हैं।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, in his statement, the hon. Minister, in reply to the first question, has stated that the Government is interested in the resumption of the composite dialogue with Pakistan. There is no doubt that the cross-border terrorism is the biggest menace to the security in the post cold-war era. For the last ten years, as the Minister has correctly admitted, some sort of a proxy war is being carried on from Pakistan. Even the new junta in Pakistan has described Kashmir as the flash point.

My question in this regard is: How will you resume the composite dialogue with Pakistan, which is needed to resolve this issue? We may like it or we may not like it, the hard fact is the Pakistan is our neighbour. It is also a nuclear-weapon state. The sub-continent, wittingly or unwittingly, has been the breeding ground of nuclear proliferation. In that context, what steps have you taken to resume the composite dialogue? The dialogue has been suspended.

We are told through newspapers that you are very much concerned about the character of the Government there. I do not know if, in our diplomacy or in our foreign policy, we ever took into account the character of the ruler, especially so in Pakistan. Since 1947, out of 52 years, in that country, for as many as 33 years there had been the army rule, and we had to deal with the army rule. We may like it or we may not like it.

I want to know from the hon. Minister whether this perception that the Government of India will not like to resume the dialogue with the military ruler in Pakistan, is standing in the way of the resumption of the composite dialogue with Pakistan, which will cover not only the cross-border terrorism but also restraining the terrorist outfits operating from Pakistan and Pakistan providing all logistic support including training, equipment, shelter and money. Is this approach standing in the way of the resumption of the dialogue? Is there any possibility of the resumption of the dialogue that you want in the Lahore spirit? If so, what steps, what initiatives is the Government of India taking?

SHRI GEORGE FERNANDES: There can be no two opinions on the fact that one has to settle problems by dialogue. As the hon. Member himself has said, there have been dialogues during the 33 years Pakistan has been under the military rule.

Sir, the stand taken by the Government was in the aftermath of Kargil. After all, pre-Kargil, there have been exchange visits. We have had the Defence Secretary of Pakistan visiting India and the Indian Defence Secretary went to Islamabad. A dialogue was initiated at various levels. These meetings took place, and the Lahore process, as it is known, began in February. And by April end or early May, we had this problem. It is consequent upon that, in other words, the total breach of trust. In certain respects, that breach or trust occurred after 27 years of trust. It is that which prompted the

Government to take the position that any resumption of the dialogue must be preceded by a demonstration of good intentions. Today, the only manner in which Pakistan can demonstrate that intention is by stopping the cross-border terrorism. We are also losing men. During the year that is just coming to an end in a couple of days, we have killed 1006 terrorists or militants. But, we also lose men. We also lost 200 men in the process. There is not a single day of the year when we do not have cross-border firing. This firing is resorted to by them in order to send militants into the country. In that kind of a situation, to simultaneously say "let us meet in Lahore or in Delhi and keep talking", does not make any sense. If Pakistan demonstrates its good intentions of wanting to bring about a settlement on whatever issue it is that we need to settle between the two countries, then a dialogue is possible. That is precisely why in this reply I have said that Pakistan has to put an end to cross-border terrorism before we can really resume the dialogue.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, while speaking on this important question, I would like to say that there were reports in the media sometimes back that there was a massive congregation of all these terrorists and protestors who are operating within India and within Pakistan, with the aim of so-called liberation of Kashmir. The Pakistani rulers also attended that congregation and, in fact, promised for the first time that they will extend all the support necessary for the cause of these people and these organisations. I would like to know whether the Government of India is aware of that. If so, what are the steps that the Government of India has taken to expose. Pakistan through international fora and create the needed atmosphere among the international community also to bring pressure on Pakistan to desist from aiding and abetting terrorism. I say this because an open declaration by the Pakistani rulers that they will aid and abet terrorism and will give all necessary support is a very serious issue. I would like to know whether the Government of India is aware of such a conference having taken place. If so, what are the steps taken. The hon. Minister has said that the international community is also being kept apprised of Pakistan's continued support to terrorism. In what form have they been able to communicate with the international community and in what way have we taken up the matter with the international community?

SHRI GEORGE FERNANDES: Sir, support of the Pakistani rulers to terrorism is not a new thing. The meeting that they had at Muree, near Lahore, recently, which has brought about this question, is not the first one. They have had such meetings earlier also. The Pakistani Government is directly involved in whatever that is being done by the militants in Kashmir. It is a well-known fact.

Over the years, even while fighting this proxy war, India has made diplomatic efforts at the global level. Every country, that wants to listen, has been briefed and is continuously being briefed in various international conferences. Pakistan has tried to raise this issue and we have succeeded in preventing any bilateral issue between Pakistan

and ourselves being raised in any international conference. So, there is a consistent effort on the part of the Government of India at the diplomatic level to tell all those countries which are concerned about terrorism, generally, and about cross-border terrorism, particularly, of the implications of what Pakistan is indulging in. I believe we have succeeded in convincing these countries across the world of Pakistan's evil designs. In the case of Kargil, also we went through this exercise. I do believe that the diplomatic efforts on the part of India enable us to get the support of a large number of very important countries, when we were fighting the Pakistani aggression in Kargil just a few days back.

SHRI NILOTPAL BASU: Mr. Chairman, Sir, there are two aspects which need a little clarification. First of all, in response to Mr. Janeshwar Misra's supplementary, the Defence Minister was kind to tell us that there was no direct communication from Pakistan about all these activities. Now, there are so many questions agitating the Indian mind about the exact role of the Indian intelligence agencies during the period of Kargil war. We have also come to know that the Government has constituted a committee, under the Chairmanship of Mr. K. Subrahmanyam, to go into all these things. Now, what are the findings of the Committee? May I know from the Defence Minister whether the Government is prepared to place the report of the Subrahmanyam Committee on the Table of the House?

Then (b) part of my question is : We have heard about the National Security Council meeting only on the 8th June, though it was formed in October, 1998. Now, in this entire exercise of our strategic defence review, embracing comprehensive aspects of national security, particularly, in the post-Kargil scenario, when is the National Security Council going to meet to consider these things? When will the country be informed that the new institutional framework will take into account all these developments?

SHRI GEORGE FERNANDES: Sir, in sofar as the Subrahmanyam Committee's report is concerned, we are expecting that report any day. Only after the Government has studied that report, I will be able to let the House know what exactly the decision on that report is.

Regarding the National Security Council meeting, well, it did meet on the 8th June. The Government had the benefit of getting the advice of the National Security Council. On a continuing basis, such advice is available.

SHRI NILOTPAL BASU: When is the next meeting of the National Security Council? During its entire tenure of existence, it has met only once.

SHRI GEORGE FERNANDES: Sir, I cannot possibly announce about the next meeting in the House.

श्रीमती कमला सिन्हा: सभापति जी, मेरे सवाल का मंत्री जी ने आंशिक रूप से जवाब दे दिया, फिर भी मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या भारत सरकार को इसकी जानकारी है कि अफगानिस्तान, जो हमारा पड़ोसी देश है के अंदर एक लंबे अरसे से पाकिस्तान के फौजी अफसर ट्रेनिंग दे रहे हैं जिन्हें आप

मुजाहिदीन या टेरेरिस्ट फोर्स कह सकते हैं। ये ट्रेनिंग फोर्स They are not necessarily Pakistanis. They are drawn from many other countries also. हमारे क्रोस बोर्डर में भी आते हैं और ये दूसरी जगह फैल रहे हैं। क्या गवर्नमेंट इस दिशा में कोई स्टेप उठा रही है कि अफगानिस्तान या दूसरे देशों में इस तरह की ट्रेनिंग बंद हो?

श्री जार्ज फर्नांडीज: सभापति जी, पाकिस्तान के जो ट्रेनिंग कैम्पस हैं उनके बारे में हम पाकिस्तान को बार-बार बताते आए हैं कि अमुक-अमुक स्थानों पर उनकी तरफ से काम हो रहा है। अगर अन्य किसी स्थान से भी जब आतंकवादियों को भारत में भेजने का प्रयास पाकिस्तान की ओर से होता है तो उसकी जानकारी भी उन्हें दे दी जाती है लेकिन जो नतीजे हैं वे अपनी जगह हैं।

DR. MANMOHAN SINGH: Mr. Chairman, Sir, I draw the hon. Minister's attention to a newspaper report which has appeared a few days ago to the following effect that the latest attack on the Rashtriya Rifles Headquarters in Baramulla District is the proof, if one was needed, after a series of attacks on the security forces, that despite assurances to the country, the Government has not been able to prevent the infiltration of a large number of professional mercenaries across the border. May I know from the Defence Minister what is his assessment regarding the continuous inflow of these professional mercenaries? The Defence Minister has also said that they have suspended the dialogue with the Government of Pakistan. Then, would he kindly tell us what precise measures the Government is adopting to check the increasing flow of these professional mercenaries from Pakistan?

श्री जार्ज फर्नान्डीज: सभापति जी, यह तो एक अरसे से चला हुआ पाकिस्तान की तरफ से प्रयास है कश्मीर में बाहर से अथवा काश्मीर से बाहर ले जा कर प्रशिक्षण दे कर के तैयार हुए आतंकवादियों को अंदर भेजने का। गर्मी के दिनों में इसमें बढ़ावा होता है। क्रॉस बार्डर फायरिंग हर दिन होती है। इसके पीछे भी यही मुख्य कारण है कि फायरिंग कर के हमारी चौकियों पर तैनात जवानों को पाकिस्तान की चौकियों से आई हुई फायरिंग का मुकाबला करने के लिए व्यस्त रख कर जहां से भी संभव हो आतंकवादियों को घुसेड़ने का बहुत सालों से चला हुआ प्रयास है। इसका जो भी मुकाबला करना है, वह मुकाबला होता रहा है। इससे अंदर आते हुए आतंकवादी मारे जाते हैं, अंदर आने के बाद भी मारे जाते हैं। मगर यह बात सही है कि कभी-कभी घटनाएं घटती हैं जैसे बारामुला का जिक्र माननीय सदस्य ने किया ....(**व्यवधान**)

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU: Sir, there is no translation. (*Interruptions*).

श्री वायालार रवि: अंग्रेजी में बोलिये।

SHRI GEORGE FERNANDES: The hon. Member referred to the incident in Baramulla. (*Interruptions*).

SHRI VAYALAR RAVI: It is okay now.

श्री रामदेव भंडारी: राष्ट्रभाषा को छोड़ कर विदेशी भाषा में बोल रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्रीमती कमला सिन्हा: हिन्दी में तो बोल ही रहे थे। (**व्यवधान**)

SHRI GEORGE FERNANDES: Sir, there has not been just the Baramulla incident. In the past two or three months, there have been two or three similar incidents. Those incidents have been some kind of desperate attacks which were launched by these terrorists and small groups of terrorists. Now, Sir, in a situation of the type we face in Kashmir, such developments or such situations are bound to be there, such incidents are bound to be there. I do not think one should be overtly exercised when a country which has been very badly beaten in Kargil, is, today, making a desperate attempt to show that it is still able to create difficulties in Kashmir. But, Sir, overall, the situation in Kashmir has improved to a point where tourism is flourishing in the State, where the Amar Nath Yatra has been held continuously for the last two years now with tremendous success, where people are, once again, able to resume their normal activities, where life is moving, by and large, in a normal way. So, Sir, I believe that while Pakistan, through its militants, may try to indulge in occasional demonstrative action apart from what is happening on the borders, there is no reason for any kind of anxiety.

श्री गया सिंह: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। पिछली बार जो घटनाएं कारगिल में हुई, उसकी चिंता देशवासियों को है। अभी भी कश्मीर के अन्दर कोई दिन ऐसा नहीं होता है जब बड़े अफसरों और हमारे कैंपों पर हमले नहीं होते। सवाल के पार्ट (ग) में यह पूछा गया है कि किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है। आज भी क्रॉस बार्डर और अंदर जो घटनाएं हो रही हैं, लोग हर रोज मारे जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि स्थिति सुधर रही है। आपने कौन सा उपाय किया है जिससे दोबारा कारगिल न हो। बार्डर से अभी भी किसी तरह से चकमा दे कर के वह आ रहे हैं, उस पर आप रोक लगा सकें, इसके लिए आप क्या ठोस कार्यवाही कर रहे हैं, क्या उपाय कर रहे हैं?

श्री जार्ज फर्नान्डीज: सभापति महोदय, मैंने शुरू में ही कहा कि कश्मीर में जो चीज चल रही है यह तो पिछले 10 सालों का मामला है। इसका सामना करने का काम भी लगातार चला आया है। कारगिल पर आक्रमण पाकिस्तान की ओर से जो किया गया, उसका जवाब उस क्षेत्र में दे कर के उसको बैठा दिया है। हम यह मानते हैं कि पाकिस्तान फिर कभी ऐसा और कोई प्रयास नहीं कर सकेगा और न ही करना चाहेगा, चाहे बोलने के लिए कुछ भी कहे, यह बोलने की बातें हैं। उनके अपने देश में कारगिल को ले कर एक वातावरण बना है तो उस पर भी बात करने के लिए कहा जाता है। यह सब दुनिया जानती है। मगर सीमाओं पर और कश्मीर में जो आतंकवाद का प्रयास चल रहा है उसका सामना करने के लिए हमारी सेना वहां पर तैनात है और काबिल भी है।

***मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी:** थैंक्यू सर, सदरे मोहतरम, हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कारगिल की जंग ही के जमाने में एक बयान दिया था कि कारगिल में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का हाथ नहीं है बल्कि वहां की मिलिट्री और आई॰एस॰आई॰ इस जंग के लिए जिम्मेदार हैं, पाकिस्तान की सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं सर, कि आज तो पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, जम्हूरियत का कत्ल हो चुका है। जो लोग हमारे हिंदुस्तान के फौजियों के कातिल हैं, हमारी जमीन हड़पने वाले काबिज लोग हैं, आज उसी मिलिट्री और आई॰एस॰आई॰ की पाकिस्तान में हुकूमत है। तो क्या

* Transliteration of the Speech in Persian Script is available in the Hindi version of the Debate.

उस मिलिट्री से और आई॰एस॰आई॰ से जिसने हमारे मुल्क के अम्न को जंग के माहौल में बदलकर पूरे हिंदुस्तान ही को नक्जे आलम का निशाना नहीं बनाया बल्कि पूरी दुनिया में अपने आतंकवाद का एक चिह्न पैदा किया है, तो क्या ऐसी हुकूमत से,—जो हुकूमत खुद कारगिल की जंग की डायरेक्ट जिम्मेदार है, आज जो हुकूमत है, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब के कहने के मुताबिक हम मानते भी हैं-निपटने में हमारी हुकूमत क्या कठोर कार्यवाही करेगी जिससे पाकिस्तान के आतंकवाद के सारे सुराख बंद किए जा सकें?

श्री जार्ज फर्नान्डीज: सभापति जी, इनकी हुकूमत से हमारी कोई जंग नहीं है और न हो सकती है। वह तो उनके देश के भीतर वे किस प्रकार की हुकूमत बनाए रखें यह तो पाकिस्तान के लोगों का कार्य है। जहां तक हमारे देश के साथ उनका जो बर्ताव हो रहा है, विशेषकर काश्मीर के इलाके में, उसका सवाल है तो उसका जवाब तो हम लोग देते आए हैं और देते रहेंगे।

SHRI JANARDHANA POOJARY: Sir, I would like to have one clarification from the Minister relating to Q. No. 341.

MR. CHAIRMAN: No, no. We have already consumed half an hour on this question. Now, Question No. 342.

Restoration of rural infrastructure in Orissa

*342. DR. M.N. DAS: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have taken note of the severe devastation over extensive rural areas in Orissa due to the Super-Cyclone of 29th-30th October, 1999; and

(b) if so, whether Government have contemplated comprehensive measures to restore rural infrastructure in the affected areas?

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI SUNDAR LAL PATWA): (a) Yes, Sir.

(b) The state of Orissa has been allocated an amount of Rs. 56.67 crore in the Calamity Relief Fund for the current year, consisting of Rs. 42.50 crore as Central contribution and Rs. 14.17 crore as State share. Entire Central share of Rs. 42.50 crore has been released. Further, an amount of Rs. 500 crore has been released on adhoc basis from the National Fund for Calamity Relief suspending the laid down procedure. Besides, an amount of Rs. 450 crore has also been released to the State as advance plan assistance.

In addition, Ministry of Rural Development has released an amount of Rs. 146.09 crore as advance instalments for implementing the programmes of the Ministry which, *inter alia,* would help in rehabilitation/reconstruction. The Ministry has indicated to Government of Orissa that one more instalment can be released after the State Government gives feedback on the utilisation and situation with regard to rural development schemes. The following programmes relate to rural infrastructure. The